



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 वैशाख 1945 (श0)  
(सं0 पटना 392) पटना, शुक्रवार, 12 मई 2023

#### स्वास्थ्य विभाग

बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली, 2023

अधिसूचना

12 मई 2023

सं० 11/मा०(विविध)-07/2017-371(11)—मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 121 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बिहार सरकार एतद् द्वारा, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात:-

#### अध्याय-I

##### 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ —

- संक्षिप्त शीर्षक**— ये नियमावली बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली, 2023 कही जाएगी।
- विस्तार**— इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- प्रारंभ**— यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिस तिथि से बिहार सरकार अपने आधिकारिक गजट में अधिसूचित करें।

##### 2. परिभाषाएं,— (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- “अधिनियम”** से अभिप्रेत है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017(2017 का 10);
- “बोर्ड”** से अभिप्रेत है मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड;
- “प्रपत्र”** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रपत्र;
- “गैर-सरकारी सदस्य”** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (1) के खण्ड (छ) से (ढ) के अन्तर्गत नामांकित राज्य प्राधिकरण के सदस्य;
- “विहित”** से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-123 के अन्तर्गत विहित विनियम;
- “विनियम”** से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-123 की उप-धारा (1) के अधीन अधिनियम के प्रावधानों को लागू किए जाने के लिए निर्गत विनियम;
- “नियम”** से अभिप्रेत है “बिहार मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली, 2023”;

- (ज) “धारा” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;  
 (झ) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है बिहार की राज्य सरकार;  
 (ञ) “राज्य प्राधिकरण या प्राधिकरण” से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-45 के तहत गठित बिहार राज्य का राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं अथवा यथास्थिति, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (1970 का 48) में परिभाषित हैं, जहाँ तक कि वे अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या यथास्थिति, उन अधिनियमितियों में उनके लिये समनुदेशित हैं।

## अध्याय-II

### राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

3. **राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की संस्थापना:**— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक प्राधिकरण की स्थापन करेगी जिसे राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में जाना जाएगा।
4. **राज्य प्राधिकरण की संरचना:**—(1) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा,—
  - (क) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग का सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव—पदेन अध्यक्ष;
  - (ख) राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग में मानसिक स्वास्थ्य का प्रभारी संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;
  - (ग) स्वास्थ्य सेवाएं या चिकित्सा शिक्षा का निदेशक प्रमुख—पदेन सदस्य;
  - (घ) राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव—पदेन सदस्य;
  - (ङ) अधिनियम की धारा-46 की उप-धारा (1) खंड (ड) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नामित गृह विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी—पदेन सदस्य;
  - (च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला राज्य के किसी मानसिक अस्पताल का प्रमुख या किसी सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के मनश्चिकित्सा विज्ञान का विभागाध्यक्ष—सदस्य;
  - (छ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला ख्यातिप्राप्त राज्य का एक मनश्चिकित्सक जो सरकारी सेवा में नहीं हो—सदस्य;
  - (ज) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (थ) की मद (iii) में यथा परिभाषित एक ऐसा मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;
  - (झ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;
  - (ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ऐसा नैदानिक मनोविज्ञानी जिसके पास उस क्षेत्र का कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;
  - (ट) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाली एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स, जिसके पास उस क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो—सदस्य;
  - (ठ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले दो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधि हों जो मानसिक रूग्ण हैं या रहे थे—सदस्य;
  - (ड) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले या देख-रेख कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के दो व्यक्ति—सदस्य;
  - (ढ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाले ऐसे गैर-सरकारी संगठनों का जो मानसिक रूग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति—सदस्य;
- (2) राज्य सरकार, द्वारा उप-धारा (1) के खंड (ङ) से खंड (ढ) में निर्दिष्ट सदस्यों को ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए।
5. **राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के चयन का मानदंड:**—किसी व्यक्ति का राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में चयन तभी किया जाएगा, जब वह—
  - (i) भारत का नागरिक हो;
  - (ii) 67 वर्ष की आयु से अधिक का न हो;
  - (iii) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली 2018 के नियम 5 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव प्राप्त हो;
6. **राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करना:**—राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य के पद हेतु रिवित्त को खुले विज्ञापन के माध्यम से राज्य में कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों (एक

- अंग्रेजी तथा एक स्थानीय भाषा), जिसका राज्य में विस्तृत परिसंचरण होता है, में व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा तथा इस विज्ञापन को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
7. **राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु चयन समिति:**—राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु चयन समिति में एक अध्यक्ष, जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, तथा राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में अनुभव हो।
8. **राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु प्रक्रिया:** (1) नियम 7 के तहत गठित चयन समिति, विभाग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी तथा उन आवेदनों की संवीक्षा करेगी, जो धारा 46, नियम 4 और नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।
- (2) चयन समिति द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के प्रावधानों के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में चयनित होने वाले आवेदकों की उपयुक्तता पर निर्णय किया जाएगा।
- परंतु नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्ति के मामले में उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसे मानसिक रूग्ण व्यक्तियों का उपचार करने का 10 वर्ष का अनुभव हो।
- (3) राज्य सरकार, चयन समिति द्वारा राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चयनित व्यक्तियों का नाम निर्देशन करेगी।
9. **सेवा की शर्तें—(1) गैर-सरकारी सदस्य:**—अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (1) के खंड (च) से (ढ) में निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के सदस्य नामांकन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे एवं पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;
- परंतु कोई सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस रूप में पद धारण नहीं करेगा।
- (2) **पदेन सदस्य:**— राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य पदेन सदस्य, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में तब तक पद धारण करेंगे, जब तक की वह उस पद पर रहते हैं जिसके आधार पर उन्हें नामित किया गया है।
- (3) **त्यागपत्र:**—राज्य प्राधिकरण का कोई सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा;
- परंतु कोई सदस्य, जब तक उसे राज्य सरकार द्वारा अविलम्ब पदत्याग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के अवसान तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति के पदग्रहण किए जाने तक या उसकी पदावधि के अवसान तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करता रहेगा।
- (4) **रिक्तियों का भरा जाना:**—राज्य सरकार, रिक्ति को भरने के लिए, राज्य प्राधिकरण के किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या हटाए जाने के कारण किसी रिक्ति के होने की तारीख से दो मास के भीतर और प्राधिकरण के किसी सदस्य की अधिवर्षिता या पदावधि पूरी होने के तीन मास पूर्व नामनिर्देशन कर सकेगी।
- (5) **राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए भत्ते:**— प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य राज्य प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के लिए बैठक भत्ता के रूप में रुपये 2 हजार (रुपये दो हजार) मात्र एवं उस यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का हकदार होगा, जो राज्य सरकार के वेतन स्तर-11 के पदाधिकारियों को लागू होता है।
10. **राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी:**— (1) राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरण के लिए एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो राज्य के उप सचिव से अन्यून स्तर का होगा।
- (2) राज्य प्राधिकरण, राज्य सरकार के अनुमोदन से, राज्य प्राधिकरण द्वारा उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित कर सकेगा।
- (3) राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य नियम और शर्तों (जिसके अंतर्गत अर्हताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति भी हैं) वे होंगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।
11. **राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कृत्य:**— (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य प्राधिकरण का विधिक प्रतिनिधि होगा और वह—
- (क) राज्य प्राधिकरण के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन;
- (ख) राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कार्य संबंधी कार्यक्रमों और विनिश्चयों के कार्यान्वयन;
- (ग) राज्य प्राधिकरण के कार्य संबंधी कार्यक्रमों के प्रस्ताव को लेखबद्ध करने;
- (घ) राज्य प्राधिकरण के राजस्व और व्यय का विवरण तैयार करने और बजट का निष्पादन करने, के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रत्येक वर्ष राज्य प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए—
- (क) पूर्व वर्ष में प्राधिकरण के सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए एक साधारण रिपोर्ट;

- (ख) कार्य के कार्यक्रम;
- (ग) पूर्व वर्ष के वार्षिक लेखे; और
- (घ) आगामी वर्ष के लिए बजट, प्रस्तुत करेगा।
- (3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

**12. राज्य प्राधिकरण की कृत्यः—**(1) राज्य प्राधिकरण—

- (क) धारा 43 में निर्दिष्ट मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के सिवाय राज्य के सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत करेगा और ऐसे संस्थानों के पंजी का संधारण और प्रकाशन करेगा (जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर आनलाइन प्रकाशन भी है);
- (ख) राज्य के विभिन्न प्रकारों के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए गुणवत्ता और सेवा व्यवस्थापन के मानक विकसित करेगा;
- (ग) राज्य के सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का पर्यवेक्षण और सेवाओं की व्यवस्था में कमियों के बारे में शिकायतें प्राप्त करेगा;
- (घ) राज्य में मानसिक स्वास्थ्य वृत्तियों के रूप में कार्य करने के लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिकों, मानसिक स्वास्थ्य नर्सों और मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को पंजीकृत करेगा और ऐसे पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तियों की सूची, ऐसी रीति में प्रकाशित करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;
- (ङ) इस अधिनियम के उपबंधों और उनके क्रियान्वयन के बारे में विधिक प्रवर्तन पदाधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तियों और अन्य स्वास्थ्य वृत्तियों सहित सभी सुसंगत व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेगा;
- (च) मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जिनका राज्य सरकार विनिश्चय करे, निर्वहन करेगा;

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत राज्य के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को (उनको छोड़कर जो धारा 43 में निर्दिष्ट हैं) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पंजीकृत हुआ समझा जाएगा और ऐसे पंजीकरण की प्रति राज्य प्राधिकरण को दी जाएगी।

- (2) इस धारा के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे पंजीकरण के लिए आरोपित फीस भी है) वह होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

**13. राज्य प्राधिकरण की बैठकेंः—**(1) राज्य प्राधिकरण की बैठक (एक वर्ष में कम से कम चार बार) ऐसे समय और स्थानों पर होगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों की गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

- (2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से, राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उपस्थिति होने में असमर्थ है, तो वरीयतम् सदस्य प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (3) राज्य प्राधिकरण की किसी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।
- (4) राज्य प्राधिकरण के सभी विनिश्चय अध्यक्ष या राज्य प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होंगे।
- (5) यदि कोई सदस्य, जो किसी कंपनी का निदेशक है और उसके ऐसे निदेशक के रूप में राज्य प्राधिकरण की बैठक में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र ऐसी बैठक में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसे प्रकटन को प्राधिकरण की कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाएगा और वह सदस्य उस विषय के संबंध में राज्य प्राधिकरण के किसी विचार—विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

**14. जानकारी उपलब्ध कराना—**राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित सूचना आवधिक रूप में या जब भी इसको आवश्यकता हो, मांग सकेगी और राज्य प्राधिकरण या बोर्ड, यथास्थिति प्रपत्र—क में ऐसी सूचना देगा।

**अध्याय—III**

**मानसिक स्वास्थ्य वृत्तियों की योग्यता**

15. **“मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक”**— राज्य सरकार निम्नांकित वृत्तिकों को मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक के रूप में मान्य करेगी—
  - (i) खंड (भ) में यथा परिभाषित कोई मनश्चिकित्सक; या
  - (ii) धारा 55 के अधीन संबद्ध राज्य प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कोई वृत्तिक; या
  - (iii) कोई ऐसा वृत्तिक जिसके पास मनोविज्ञान एवं मानस रोग में स्नातकोत्तर डिग्री (आयुर्वेद) या मनोरोग-विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री (होम्योपैथी) या मौलिजत (नफासियत) में स्नातकोत्तर डिग्री (यूनानी) या सिरापू मारुथुवम में स्नातकोत्तर डिग्री (सिद्ध) है;
16. **मनोचिकित्सक होने की मान्यता**—राज्य सरकार किसी ऐसे चिकित्सक को इस अधिनियम की धारा (2) की उप-धारा (1) के खण्ड (म) के अंतर्गत अधिनियम के प्रयोजन से मनोचिकित्सक के रूप में मान्यता देगी, जिसके पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई या राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई या मान्यता प्राप्त और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची में सम्मिलित या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अथवा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अधीन गठित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मनोचिकित्सक की स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा है और इसके अंतर्गत किसी राज्य के संबंध में कोई ऐसा चिकित्सा पदाधिकारी भी सम्मिलित है जिसको राज्य सरकार ने मनोचिकित्सा में उसके ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मनोचिकित्सक घोषित कर दिया है।
17. **नैदानिक मनोचिकित्सक के लिये योग्यता**—(1) अधिनियम की धारा-2 की उप-धारा के खण्ड (छ) के अधीन मनोचिकित्सक की योग्यता—(i) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय पुनर्वास परिषद् द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त किसी संस्था से नैदानिक मनोविज्ञान की मान्यता प्राप्त अर्हता या मनोविज्ञान; या
  - (ii) मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जो नैदानिक मनोविज्ञान या आयुर्विज्ञान और सामाजिक मनोविज्ञान में मास्टर ऑफ फिलोसफी जो दो वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त और भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम, 1992 (1992 का 34) द्वारा अनुमोदित और मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण या ऐसी मान्यता प्राप्त अर्हताएं, जो विहित की जाएं, भी हैं, पूरा करने के पश्चात प्राप्त की गयी हो।
18. **मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता के लिये योग्यता**—अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (भ) के अधीन मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता हेतु योग्यता, सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री और मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्य में मास्टर ऑफ फिलोसफी होगी, जो दो वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षित नैदानिक प्रशिक्षण या ऐसी मान्यता प्राप्त योग्यता जो विहित की जाएं, पूरा करने के पश्चात प्राप्त की गयी हो।
19. **मानसिक स्वास्थ्य नर्स**—अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (थ) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य नर्स की योग्यता होगी— वैसे व्यक्ति जिसके पास भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का 48) के अधीन स्थापित भारतीय नर्स परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त साधारण परिचर्या में डिप्लोमा या डिग्री या मनश्चिकित्सीय परिचर्या में डिप्लोमा या डिग्री है और वह राज्य की सुसंगत नर्स परिषद् में उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है।
20. **मानसिक स्वास्थ्य संस्थान**— अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (त) के अधीन आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सहित कोई ऐसा स्वास्थ्य संस्थान अभिप्रेत है जो पूर्णतः या अंशतः मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों की देख-रेख के लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, न्यास, चाहे निजी हो या सार्वजनिक, निगम, सहकारी सोसायटी, संगठन या किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या अनुरक्षित किया गया है, जहां मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति देख-रेख, उपचार, स्वास्थ्य लाभ और पुनर्वासन के लिए, अस्थायी रूप से या अन्यथा भर्ती किये जाते हैं, और रहते हैं या रखे जाते हैं; और इसके अंतर्गत राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, न्यास चाहे निजी हो या सार्वजनिक, निगम, सहकारी सोसायटी, संगठन या किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा स्थापित या अनुरक्षित साधारण अस्पताल या साधारण परिचर्या गृह भी हैं, किन्तु इसके अंतर्गत पारिवारिक निवास स्थान नहीं है जहां मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति अपने रिश्तेदारों या मित्रों के साथ निवास करता है।
21. **मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का अनंतिम पंजीयन**—(1)राज्य के प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक का पंजीयन राज्य प्राधिकरण में किया जाएगा।

- (2) उपरोक्त नियम 15 में निर्दिष्ट प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ फार्म—(च) में राज्य प्राधिकरण को अनंतिम पंजी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें शुल्क के साथ विवरण शामिल होगा।
- (3) राज्य प्राधिकरण, इस बात से संतुष्ट होने पर की मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक अधिनियम की धारा—2 की उप-धारा(1) के खंड (द) में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पुरा करता है, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक को अनंतिम पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।

#### अध्याय—IV

#### राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों हेतु अनंतिम पंजीकरण

22. **राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के अनंतिम पंजीकरण की प्रक्रिया—**(1) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के तहत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, को छोड़कर, राज्य में प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को राज्य प्राधिकरण के तहत पंजीकृत किया जाएगा।
  - (2) उप-नियम (1) के संदर्भ में प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अनंतिम पंजीकरण हेतु आवेदन उस स्थान, जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है, को देय राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित मांग देय ड्रॉपट के माध्यम से बीस हजार रुपये के शुल्क के साथ फार्म—बी जिसमें सभी विनिर्दिष्ट ब्योरा निहित है, में राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
  - (3) राज्य प्राधिकरण यह संतुष्ट होने पर कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान अधिनियम की धारा 65 और 66 में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है, ऐसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को फार्म—सी में एक अनंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा।
23. **पंजीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता और नवीकरण—** नियम 11 के उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रदत्त अनंतिम पंजीकरण प्रमाण-पत्र ऐसे प्रदान करने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा और इस प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन इस प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व तीस दिनों के भीतर फार्म—बी में करना होगा तथा यदि इस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन नहीं किया जाता है तो संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण को राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित नवीकरण शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
24. **नियमित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र—** यदि कोई मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान अनंतिम पंजीकरण अवधि के दौरान सभी मापदण्डों को पुरा करता है और नियमित पंजीकरण के लिए इच्छुक है, तो वह निर्धारित शुल्क के साथ प्रपत्र—आई में, नियमित पंजीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है और प्राधिकरण संतुष्ट होने पर ऐसे संस्थान को फार्म— सी में नियमित पंजीकरण का प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जो ऐसे प्रमाण-पत्र के लाईसेंस की तारीख से पाँच साल के लिए वैध होगा।
25. **नियमित पंजीकरण का नवीनीकरण—**किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के नियमित पंजीकरण का पाँच साल के नवीनीकरण किया जा सकता है, यदि संस्थान फार्म— आई में नियमित पंजीकरण की समाप्ति की अंतिम तिथि से पहले, छः महीने के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करता है, अन्यथा नियमित पंजीकरण की समाप्ति के बाद यह समाप्त हो जाएगा और संबंधित संस्थान को नये सिरे से अनंतिम पंजीकरण कराना होगा।
26. **डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी करना—** यदि किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण नष्ट हो जाता है या गुम हो जाता है या विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो, ऐसे संस्थान द्वारा राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है, में देय एक मांग देय ड्रॉपट के माध्यम से दो हजार रुपये के शुल्क के साथ आवेदन करने पर राज्य प्राधिकरण डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी।
27. **डिजिटल रजिस्टर का अनुरक्षण—** (1) सभी पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का श्रेणीवार रजिस्टर प्रपत्र—घ में, अधिनियम की धारा 71 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल प्रारूप में राज्य प्राधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।
  - (2) सभी पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का श्रेणीवार रजिस्टर प्रपत्र—ड में, अधिनियम की धारा 55 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल प्रारूप में राज्य प्राधिकरण द्वारा संधारित किया जायेगा।
  - (3) मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों के पंजीयन हेतु आवेदन, प्रपत्र—च में, तीन हजार रुपये के शुल्क, अध्यक्ष, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्रापट के माध्यम से, उस स्थान में देय, जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है, संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा।
  - (4) प्रपत्र—छ, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा वृत्तिकों को जारी किये जाने वालों पंजीयन प्रमाण-पत्र हेतु प्रपत्र है। निर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) में दी गई शर्तों और इसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के अध्यक्षीन होगा तथा इसकी वैधता, इसके जारी होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए होगी और अवधि की समाप्ति के एक माह पूर्व निर्धारित शुल्क के साथ नवीनीकरण किया जा सकेगा।

- (5) अधिनियम की अपेक्षाओं की प्रतिपूर्ति होने में राज्य प्राधिकरण, प्रचलित विधियों, मानकों, नियमों और विनियमों का ध्यान रखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की पंजी की रजिस्टर, अग्रिम निर्देशों, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान आदि के ऑनलाईन सृजन एवं प्रचालन के संबंध में समय-समय पर तत्संबंधी ऑनलाईन डाटाबेस या पोर्टल हेतु विनियम या अधिसूचना निर्गत करेगा।

#### अध्याय—V

##### वित्त, लेखा एवं लेखा-परीक्षा

28. **राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरण को अनुदान.**—राज्य सरकार, विधायिका द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा, किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात्, राज्य प्राधिकरण को उतनी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जितनी राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु उचित समझे।
29. (1) **“राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण निधि”** के नाम से एक कोष का गठन किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा—
- (प) केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा राज्य प्राधिकरण को दिया गया अनुदान और उधार;
- (पप) अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसों और प्रभार; और
- (पपप) ऐसे अन्य स्रोतों से राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसी सभी धनराशियाँ जिनका राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग, राज्य प्राधिकरण/बोर्ड के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक को पूरा करने और राज्य प्राधिकरण/बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके उपगत व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा।
30. **राज्य प्राधिकरण का लेखा एवं लेखा परीक्षा.**—(1) राज्य प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष से संबंधित अपनी आय एवं व्यय के लेखों का संधारण करेगा तथा आय एवं व्यय और बैलेंस शीट संबंधी लेखों का वार्षिक विवरणी तैयार करेगा।
- (2) लेखों का वार्षिक विवरणी, केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित सामान्य लेखा प्रारूप या परिस्थितियों के अनुसार लगभग वैसे ही, में प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व अथवा जैसी भी परिस्थिति हो, लेखा-परीक्षा (ऑडिट) हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (1) के अधीन तैयार किए गए लेखों के वार्षिक विवरणी पर लेखा के प्रभारी पदाधिकारी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा राज्य प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किया जाएगा और इसे राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
31. **राज्य प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन.**—(1) राज्य प्राधिकरण, अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रपत्र—ज में तैयार करेगा तथा उसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार को अग्रेसर करेगा।
- (2) वार्षिक प्रतिवेदन में पिछले वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों का सम्पूर्ण लेखा दिया जायेगा और उसमें वर्ष की लेखा-परीक्षित लेखाओं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की उस पर रिपोर्ट शामिल होगी।

#### अध्याय—VI

##### मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा-परीक्षा (ऑडिट), निरीक्षण और जाँच

32. **मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का लेखा-परीक्षा (ऑडिट).**—(1) राज्य प्राधिकरण, पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लेखा परीक्षा संचालित करवाने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा ताकि अधिनियम में विनिर्धारित न्यूनतम मानकों का इन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, नामतः—
- (क) उस जिले के समाहर्ता या जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि, जहाँ उक्त मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है;
- (ख) राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि;
- (ग) कोई मनोचिकित्सक, जो सरकारी सेवा में हैं;
- (घ) कोई मनोचिकित्सक, जो निजी प्रैक्टिस करते हैं;
- (ङ) कोई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, जो मनोचिकित्सक नहीं हैं;
- (च) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि;
- (छ) मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की देख-भाल करने वाले व्यक्तियों या देख-भाल करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि; और
- (ज) उन व्यक्तियों के प्रतिनिधि, जिन्हें मानसिक रोग हैं अथवा जो मानसिक रोग से पीड़ित थे।
- (2) पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की लेखा-परीक्षा संचालित करवाने के लिए, राज्य प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित और जहाँ राज्य प्राधिकरण स्थित है, में देय मांग के रूप में डिमाण्ड ड्रॉफ्ट के माध्यम से 10 हजार रुपये की शुल्क प्रभारित करेगा।

- 33. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण और जाँच.**—(1) राज्य प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर अधिनियम के तहत या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के गैर-अनुपालन या उसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण और जाँच का आदेश दे सकता है, नामतः —
- (क) सरकारी सेवा करने वाला कोई मनोचिकित्सक;
  - (ख) निजी प्रैक्टिस करने वाला कोई मनोचिकित्सक;
  - (ग) कोई मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, जो मनोचिकित्सक नहीं है;
  - (घ) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि;
  - (ङ) पुलिस थाना के प्रभारी पुलिस अधिकारी, जिनके अधिकार क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है;
  - (च) जिले के समाहर्ता या जिला पदाधिकारी के प्रतिनिधि, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थित है।
- (2) राज्य प्राधिकरण अथवा उप-नियम (1) के तहत अधिकृत व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति पंजीकरण के बिना मानसिक स्वास्थ्य संस्थान चला रहा है या अधिनियम के द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश और तलाशी कर सकता है।
- (3) जाँच के दौरान, राज्य प्राधिकरण अथवा इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर प्रभारी, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से राज्य प्राधिकरण के साथ अपने पंजीकरण से संबंधित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के लिए ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा।
- (4) उप-नियम (3) के तहत मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की जाँच पूर्ण होने के दो दिन के भीतर, ऐसी जाँच के निष्कर्षों की लिखित रिपोर्ट, प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।
- (5) राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष, उप-नियम (4) के तहत लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दोषी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विरुद्ध जैसा उचित समझे, कार्रवाई करेगा।

#### अध्याय—VII

##### मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड

- 34. मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन.**—(1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना के माध्यम से, राज्य के सभी 9 (नौ) प्रमण्डलों में मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड का गठन करेगा।
- (2) बोर्ड प्रमण्डलीय मुख्यालय में अवस्थित होगा।
  - (3) प्रत्येक बोर्ड का क्षेत्राधिकार संबंधित प्रमण्डल के सभी जिलों होगा।
- 35. बोर्ड की संरचना.**—प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—
- (क) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यथा नामित कोई जिला न्यायाधीश या राज्य न्यायिक सेवा का कोई अधिकारी जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित है या कोई सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;
  - (ख) उन जिलों जिनमें बोर्ड गठित किया जाना है, के जिला समाहर्ता या जिला पदाधिकारी का प्रतिनिधि;
  - (ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा नियुक्त दो सदस्य, जिनमें से एक मनोचिकित्सक और दूसरा कोई चिकित्सक होगा;
  - (घ) राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा नियुक्त दो सदस्य, जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति या देख-रेख कर्ता या मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों या देख-रेख कर्ताओं के संगठनों या मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे।
- 36. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति.**—(1) धारा 74 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए) के तहत बोर्ड के अध्यक्ष और खण्ड (सी) और (डी) के तहत बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के उद्देश्य से राज्य प्राधिकरण राज्य में व्यापक प्रसार वाले कम-से-कम दो दैनिक सामाचार पत्रों (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा) में खुले विज्ञापन के माध्यम से व्यापक प्रचार कर के आवेदन आमंत्रित करेगा और विज्ञापन राज्य प्राधिकरण के वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा;
- परंतु वैसे जिला के जिला समाहर्ता या जिला दण्डाधिकारी जहाँ बोर्ड अवस्थित है, इसके खण्ड(ख) के अंतर्गत बोर्ड के सदस्य के रूप में अपने प्रतिनिधि को नामित करेंगे।
- (2) राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप-नियम (3) के तहत प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेंगे और ऐसे आवेदनों को सूचीबद्ध करेंगे जो धारा 74 में प्रावधानित बुनियादी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उन्हें राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे।
  - (3) बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा योग्यता के अनुसार की जाएगी।



- (4) राज्य प्राधिकरण, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में रिक्ति होने से तीन महीने पहले, या जहां ऐसी रिक्ति मृत्यु या इस्तीफे या ऐसे सदस्य को हटाने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसे पद को भरने के लिए समान रीति से प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।
- (5) राज्य प्राधिकरण, समय-समय पर, बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए मानसिक स्वास्थ्य कानून, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और संबंधित क्षेत्रों में कम से कम दो कार्य दिवसों का प्रारंभिक प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था करेगा।
- 37. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें—**(1) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पाँच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (2) प्रत्येक बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- 38. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के मानदेय और भत्ते—**(1) यदि जिला न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह एक समेकित मासिक मानदेय का हकदार होगा जो कि पेंशन या पेंशन के मूल्य के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त सेवांत लाभ या दोनों उसके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक नहीं होंगे।
- (2) यदि एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह एक समेकित मानसिक मानदेय का हकदार होगा, जो कि पेंशन या सेवांत लाभ में निहित वित्तीय मूल्य के पेंशन के साथ, या दोनों ऐसे व्यक्ति द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक नहीं होगा।
- (3) यदि बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की सेवा में है, तो उसका समेकित मानदेय उसके संवर्ग के सरकारी सेवकों पर लागू नियमों के अनुसार होगा और वह केवल उस दिन के बोर्ड के बैठक के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा।
- (4) बोर्ड के प्रत्येक सदस्य, जो सरकार का सेवक नहीं है, बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और ऐसे अन्य भत्तों का हकदार होगा जो राज्य सरकार के वेतन स्तर-11 के अधिकारियों पर लागू होते हैं।
- (5) उप-नियम(1) और (2) में दिये गये को छोड़कर, अध्यक्ष या किसी सदस्य या बोर्ड को उनके द्वारा बोर्ड को की गई सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन और उपादान, स्वीकार्य नहीं होगा।
- 39. प्राधिकरण और बोर्ड के निर्णय—**(1) प्राधिकरण या बोर्ड के निर्णय, जैसा भी मामला हो, आम सहमति से होगा, जिसके न होने पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से और वोट के समानता की स्थिति में, अध्यक्ष के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा।
- (2) यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।
- 40. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें—**(1) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेंगे और पाँच वर्ष की एक और अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
- (2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।
- 41. बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य—**(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सभी या कोई विषय सम्मिलित होगा, यथा—
- (क) किसी अग्रिम निदेश को पंजीकृत करना, उसका पुनर्विलोकन, परिवर्तन, उपांतरण करना या उसे रद्द करना;
- (ख) किसी नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति करना;
- (ग) धारा 87 या धारा 89 या धारा 90 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिक या मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के विनिश्चय के विरुद्ध मानसिक रुग्णता से ग्रस्त किसी व्यक्ति या उसके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त करना और उसका विनिश्चय करना;
- (घ) धारा 25 की उप-धारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी सूचना को प्रकट न करने के संबंध में आवेदन प्राप्त करना और उनका विनिश्चय करना;
- (ङ) धारा 28 के अधीन विनिर्दिष्ट देख-रेख और सेवाओं में कमियों के संबंध में शिकायतों का न्यायनिर्णयन करना;
- (च) कारगार या जेलों का दौरा और निरीक्षण करना और ऐसे कारगार या जेल में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी चिकित्सा अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगना।
- (2) जहाँ बोर्ड या केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण के ध्यान में यह लाया जाता है कि किसी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ने मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन किया

है, वहां बोर्ड या प्राधिकरण निरीक्षण और जाँच तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्रवाई कर सकेंगे।

- (3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, प्राधिकरण से परामर्श करके मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा, जो वह समुचित समझे।
- (4) यदि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान प्राधिकरण या बोर्ड के आदेशों या निदेशों का पालन नहीं करता है या जानबूझकर ऐसे आदेश या निदेश की उपेक्षा करता है तो, यथास्थिति, प्राधिकरण या बोर्ड ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान पर शास्ति अधिरोपन कर सकेगा जो पांच लाख रूपए तक हो सकेगी और प्राधिकरण स्वमेव या बोर्ड की अनुशंसाओं पर ऐसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के रजिस्ट्रीकरण को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् रद्द कर सकेगा।
- 42. बैठकें.—** बोर्ड की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी और अपनी बैठकों में कारोबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसे प्रक्रिया एवं नियमों का पालन करेगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- 43. प्राधिकरण या बोर्ड के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील.—** प्राधिकरण या बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति या संस्थान ऐसे विनिश्चय से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य के उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा;
- परंतु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

### अध्याय—VIII

#### विविध

- 44. (1)** अधिनियम की धारा-123 के अधीन राज्य प्राधिकरण, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अधिसूचना के द्वारा अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमावली के सुसंगत विनियम बना सकती है।
- (2)** विशेष रूप से एवं पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा विनियम निम्न सभी अथवा किसी विषय पर प्रावधान कर सकता है:—
- धारा-18 की उप-धारा (9) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक;
  - राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते, तथा अन्य सेवा शर्तें (योग्यता, अनुभव तथा नियोजन की प्रक्रिया सहित);
  - धारा-55 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य वृत्तिकों की सूची प्रकाशित करेगी;
  - धारा-56 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य प्राधिकरण के बैठक का समय एवं स्थान तथा बैठक में कार्य करने के लिए (ऐसे बैठकों के कोरम सहित) प्रक्रिया का विनियम;
  - धारा-66 की उप-धारा (12) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान द्वारा किए जाने वाले आवेदन का प्रपत्र एवं इसके साथ संलग्न किए जाने वाले शुल्क;
  - धारा-66 की उप-धारा (14) के अन्तर्गत आपत्ति दायर करने की प्रक्रिया;
  - कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट होना आवश्यक है, या हो सकता है या जिसके संबंध में प्रावधान किया जाना है।
- 45.** अधिनियम की धारा-124 की उप-धारा-(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली तथा अधिनियम के तहत राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम, इसके बनाए जाने के उपरान्त यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के पटल पर रखा जाएगा।
- 46.** इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत की गयी कोई कार्रवाई अथवा किसी प्राधिकरण या बोर्ड का गठन, इस नियमावली के अन्तर्गत की गयी अथवा गठित की गयी मानी जाएगी।

बिहार के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ह०) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

**प्रपत्र-क**  
(नियम 10 देखियें)  
**राज्य प्राधिकरण/बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी**

1.	अधिसूचित नये विनियम	
2.	वर्ष के दौरान पारित ओदशों की संख्या	
3.	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें	
4.	राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और विवरण	
5.	राज्य या संघ शासित क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और विवरण	
6.	राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पंजीयन	
7.	केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त संदर्भों का विवरण और उन पर की गई कार्रवाई	
8.	राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न प्रकारों के लिए गुणवत्ता और सेवा प्रदाय मानक	
9.	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017(2017 का 10) के प्रावधानों और क्रियान्वयन के बारे में कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों सहित लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना	
10.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीयन हेतु प्राप्त, स्वीकृत तथा अस्वीकृत, अस्वीकृत किये जाने के कारण सहित, आवेदन	
11.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित	
12.	मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन संबंधी प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई	
13.	मेडिकल प्रैक्टिशनरों और मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के दिशा-निर्देश दस्तावेज संबंधी विवरण	
14.	कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 22 अधीन कार्यस्थल पर, महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के संबंध में पंजीकृत प्रकरणों की संख्या और उनका विवरण	
15.	मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण और जाँच का विवरण	
16.	प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर अपीलों की संख्या और उनकी स्थिति	
17.	सेवाओं के प्रदाय में कमी के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई	
18.	पदाधिकारियों (स्टॉक होल्डर) से परामर्श	
19.	प्राधिकरण/बोर्ड द्वारा आरंभ की गई जाँच	
20.	प्रशासनिक एवं संस्थान संबंधी मामले	
21.	बैलेंस शीट, आय एवं व्यय लेखा आदि सहित बजट और लेखा विवरण:	
22.	कोई अन्य तत्संबंधी जानकारी:	

**प्रपत्र-ख**  
(नियम 13 (2) तथा 14 देखियें)  
**मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/अनंतिम नवीनीकरण**  
**की स्वीकृति हेतु आवेदन**

सेवा में,

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
बिहार, पटना।

महोदय/महोदया,

मैं/हम.....नामक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/स्थायी पंजीयन/अनंतिम पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ/हैं, अर्थात् ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम की संस्थाना/अनुरक्षण हेतु मेरे/हमारे पास वैध लाइसेंस/पंजीयन उपलब्ध है। ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम का विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदक(कों) का नाम :.....
2. लाइसेंस जारी करने की तिथि सहित जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम का उल्लेख करते हुए लाइसेंस का विवरण :.....
3. आयु :.....
4. मनोरोग चिकित्सा में व्यावसायिक अनुभव :.....
5. आवेदक का स्थायी पता :.....
6. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का स्थान :.....
7. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का पता :.....
8. प्रस्तावित आवास :
  - (क) कमरों की संख्या :.....
  - (ख) बिस्तरों की संख्या :.....
  - (ग) प्रदत्त सुविधाएं :.....
  - (घ) बाह्य रोगी :.....
  - (ङ) आपातकालीन सेवाएं :.....
  - (च) अंतः रोगी सुविधाएं :.....
  - (छ) व्यावसायिक और मनोरंजन की सुविधाएं :.....
  - (ज) ई सी टी सुविधाएं (एन एक्स-रे सुविधाएं) :.....
  - (झ) मनोवेज्ञाविक जाँच सुविधाएं :.....
  - (ञ) परीक्षण (जाँच) और लैब सुविधाएं :.....
  - (ट) उपचार सुविधा हेतु स्टॉफ पद्धति :.....

**स्टाफ प्रणाली -**

- (क) डॉक्टरों की संख्या :.....
- (ख) नर्सों की संख्या :.....
- (ग) सहायकों की संख्या :.....
- (घ) अन्य :.....

मैं आवेदन शुल्क के रूप में .....के पक्ष में रु. ....की राशि का बैंक ड्राफ्ट एतद्वारा संलग्न कर प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

मैं एतद्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं आपसे मेरे आवेदन पर विचार करने और मनोरोग चिकित्सा अस्पताल/नर्सिंग होम की संस्थाना/अनुरक्षण हेतु लाइसेंस प्रदाय की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

भवदीय,  
हस्ताक्षर  
नाम :.....  
दिनांक :.....

प्रपत्र—ग

(नियम 13 (3) देखियें)

**अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजीयन नवीनीकरण का प्रमाण—पत्र**

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 65(2) अथवा धारा 66(3) अथवा धारा 66(10) के अधीन.....द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दिनांक—.....पर विचार करने के उपरान्त राज्य प्राधिकरण, एतद्वारा, नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार धारा 66(4) अथवा धारा 66 (11) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हेतु आवेदक को अनंतिम पंजीयन/ अनंतिम पंजीयन का नवीनीकरण प्रदान करता है :

नाम :.....

पता :.....

बिस्तारों की संख्या :.....

जारी अनंतिम पंजीयन प्रमाण—पत्र मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) और इसके अधीन सृजित नियमों और विनियमों में यथा उल्लिखित शर्तों के अध्वधीन होगा तथा इसके जारी होने की तारीख से बारह माह की अवधि के लिए मान्य होगी और इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा।

पंजीयन प्राधिकारी

पंजीयन प्राधिकरण की मुहर

स्थान :.....

दिनांक :.....

## प्रपत्र-घ

(नियम 16 देखिये)

## मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का रजिस्टर (डिजिटल प्रारूप में)

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक, सारणी .....

क्र.सं.	आवेदक का नाम व पता	संस्थान का नाम व पता	आवेदन की तारीख	पंजीयन की तारीख एवं विवरण	बिस्तरों की संख्या	टिप्पणियां

## प्रपत्र-ङ

(धारा 55 (1) (घ) देखिये)

## मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का रजिस्टर (डिजिटल प्रारूप में)

मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक, सारणी .....

क्र.सं.	आवेदक का पूरा नाम व पता	डिग्री/पी.जी.	आर.सी.आई. / एन.सी. आई./अन्य	प्रेक्टिस/कार्य का स्थान	संपर्क नंबर/ई-मेल	टिप्पणियां

- ❖ मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ताओं का पंजीयन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के अनुसार किया जायेगा।

**प्रपत्र-च**  
(नियम 16 (3) देखिये)  
**मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन**

सेवा में,

मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
बिहार, पटना।

महोदय/महोदया,

मैं.....के नाम से मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में पंजीयन/पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ :-

1. आवेदक का नाम :.....
2. संबंधित विशेषज्ञता (आर.सी.आई./एन.सी.आई.) में अर्हक डिग्री के पंजीयन का विवरण :.....  
(प्रतिलिपि संलग्न)
3. आयु :.....
4. मनोरोग चिकित्सा में व्यावसायिक अनुभव :.....
5. आवेदक का स्थायी पता :.....
6. व्यवसाय का कार्यस्थल :.....
7. शैक्षणिक योग्यता :.....

मैं आवेदन शुल्क के रूप में .....के पक्ष में रु. ....की राशि का बैंक ड्रॉप्ट एतद्वारा प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

मैं मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं मेरे इस आवेदन पर विचार करने और बिहार राज्य में मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के रूप में व्यवसाय करने हेतु पंजीयन की मंजूरी प्रदाय करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ।

भवदीय  
हस्ताक्षर  
नाम—  
दिनांक—

★ मनोरोग चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता के लिए यह लागू नहीं है।

## प्रपत्र-छ

(नियम 16 (4) देखिये)

## अनंतिम पंजीयन/अनंतिम पंजीयन के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 55(1) (घ) के अधीन.....  
द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दिनांक-.....पर विचार करने के उपरान्त राज्य प्राधिकरण, एतद्वारा, मानसिक  
स्वास्थ्य पदाधिकारी श्रेणी (वर्ग).....के रूप में आवेदक को पंजीयन/पंजीयन का नवीनीकरण प्रदान करता  
है।

पंजीयन क्र.....

नाम.....

पता.....

इस पंजीयन प्रमाण-पत्र को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) और इसके अधीन  
सृजित नियमों एवं विनियमों में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है और इसके जारी होने की तारीख से  
दस वर्ष की अवधि के लिए यह वैध रहेगी तथा इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा।

स्थान.....

दिनांक.....

पंजीयन प्राधिकारी

पंजीयन प्राधिकारी की मुहर



**प्रपत्र-ज**  
**(नियम 18 (1) देखिये)**  
**राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट**

1. प्रस्तावना,
2. प्राधिकरण के सदस्यों का प्रोफाइल,
3. विनियम का विस्तार,
4. अधिसूचित/जारी नये विनियम/प्रक्रिया इत्यादि,
5. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश,
6. वर्ष के दौरान आयोजित राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठकें,
7. राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
8. राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान,
9. राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों का पंजीयन,
10. केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अभिनिर्देशों का विवरण और उन पर की गई कार्यवाही,
11. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजे गये अभिनिर्देशों का विवरण और संबंधित सरकार द्वारा उन पर की गई कार्यवाही,
12. राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के विभिन्न प्रकारों के लिए गुणवत्ता एवं सेवा प्रदाय मानक,
13. राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का पर्यवेक्षण तथा उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कमियों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही,
14. कानून प्रवर्तन पदाधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य पदाधिकारियों सहित व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 (2017 का 10) के प्रावधानों और क्रियान्वयन के बारे में प्रदत्त प्रशिक्षण,
15. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त, स्वीकृति और अस्वीकृत, ऐसे अस्वीकृत किये जाने के कारण सहित,
16. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की लेखा-परीक्षा,
17. मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही,
18. मेडिकल प्रैक्टिशनरों और मानसिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शी दस्तावेज के संबंध में विवरण,
19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) का क्रियान्वयन,
20. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशोध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) की धारा 22 के अधीन कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के संबंध में विवरण,
21. मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण एवं जाँच,
22. प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील और उनकी स्थिति,
23. प्राधिकरण के अग्रिम दिशा-निर्देशों और अनुशंसाओं के प्रयोग की समीक्षा की स्थिति,
24. सेवाओं के प्रदाय में कमियों के विषय में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही,
25. प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई जाँच,
26. प्रशासनिक एवं संस्थान संबंधी मामले,
27. वार्षिक लेखा,
28. कोई अन्य विषय, जिन पर प्राधिकरण की राय में प्रकाश डाले जाने की आवश्यकता है।

## प्रपत्र-झ

(नियम 24 तथा 25 देखियें)

## मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के नियमित पंजीयन/ नियमित पंजीयन नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन

सेवा में,

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण,  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
बिहार, पटना।

महोदय/महोदया,

मैं/हम.....नामक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अनंतिम पंजीयन/स्थायी पंजीयन/अनंतिम पंजीयन के नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूँ/हैं, अर्थात् ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम की संस्थाना/अनुरक्षण हेतु मेरे/हमारे पास वैध लाइसेंस/पंजीयन उपलब्ध है। ऐसे अस्पताल/नर्सिंग होम का विवरण निम्नानुसार है:-

1. आवेदक(कों) का नाम :.....
2. अनंतिम/नियमित पंजीकरण प्रमाण-पत्र का विवरण तथा इसे जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम तथा दिनांक :  
.....
3. आयु :.....
4. मनोरोग चिकित्सा में व्यावसायिक अनुभव :.....
5. आवेदक का स्थायी पता :.....
6. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का स्थान :.....
7. प्रस्तावित अस्पताल/नर्सिंग होम का पता :.....
8. प्रस्तावित आवास :  
(क) कमरों की संख्या :.....  
(ख) बिस्तरों की संख्या :.....  
(ग) प्रदत्त सुविधाएं :.....  
(घ) बाह्य रोगी :.....  
(ङ) आपातकालीन सेवाएं :.....  
(च) अंतः रोगी सुविधाएं :.....  
(छ) व्यावसायिक और मनोरंजन की सुविधाएं :.....  
(ज) ई सी टी सुविधाएं (एन एक्स-रे सुविधाएं) :.....  
(झ) मनोवेज्ञाविक जाँच सुविधाएं :.....  
(ञ) परीक्षण (जाँच) और लैब सुविधाएं :.....  
(ट) उपचार सुविधा हेतु स्टाफ पद्धति :.....

## स्टाफ प्रणाली -

- (क) डॉक्टरों की संख्या :.....
- (ख) नर्सों की संख्या :.....
- (ग) सहायकों की संख्या :.....
- (घ) अन्य :.....

मैं आवेदन शुल्क के रूप में .....के पक्ष में रु. ....की राशि का बैंक ड्राफ्ट एतद्वारा संलग्न कर प्रेषित कर रहा/रही हूँ।

मैं एतद्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नियमों और विनियमों का पालन करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं आपसे मेरे आवेदन पर विचार करने और मनोरोग चिकित्सा अस्पताल/नर्सिंग होम की संस्थाना/अनुरक्षण हेतु लाइसेंस प्रदाय की मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम :.....

दिनांक :.....

*The 12<sup>th</sup> May 2023*

**The Bihar Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2023**

No. 11/मां(विधि)-07/2017-372(11)—In exercise of power conferred by sub section (2) of section 121 of the Mental Health Care Act, 2017(10 of 2017), the Government of Bihar, hereby, make following rules relating to the administration of the State Mental Health Establishments, namely :-

**CHAPTER-I**

**1. Short title, Extent & Commencement.-**

- (i) **Short Title.-** These rules may be called “The Bihar Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2023
- (ii) **Extension. -** It shall extend to the whole State of Bihar.
- (iii) **Commencement.-** It shall come into force on such date as may be notified in the Official Gazette of Bihar.

**2. Definition.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) **“Act”** means the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) of Government of India.
- (b) **“Board”** means the Mental Health Review Board constituted by the State Authority under the Act.
- (c) **“Form”** means a form appended to these rules;
- (d) **“Non-official member”** means a member of the State Authority nominated under clauses (g) to (n) of sub section (1) of section 46 of the Act.
- (e) **“Prescribed”** means prescribed by regulation issued by the State Mental Health Authority of Bihar, under section 123 of the Act.
- (f) **“Regulations”** means the regulations issued by the State Authority under sub section (1) of section 123 of the Act to carry out the provisions of this Act.
- (g) **“Rules”** means “The Bihar Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules, 2023
- (h) **“Section”** means section of the Act.
- (i) **“State Government”** means the State Government of Bihar.
- (j) **“State Authority or Authority”** means State Mental Health Authority of the State of Bihar constituted under section 45 of the Act.

- (2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or, as the case may be, in the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) or in the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act or, as the case may be, in those enactments.

**CHAPTER II**

**STATE MENTAL HEALTH AUTHORITY**

**3. Establishment of State Mental Health Authority.-** The State Government shall, by notification, Establish, for purposes of this Act, an Authority to be known as the State Mental Authority.

**4. Composition of State Mental Health Authority.-** The State Authority shall consist of the following chairperson and members:—

- (a) Secretary or Principal Secretary or Additional Chief Secretary in the Department of Health of State Government—chairperson ex officio;
- (b) Joint Secretary in the Department of Health of the State Government, in charge of mental health—member ex officio;

- (c) Director-in-Chief of Health Services or Medical Education—member ex officio;
- (d) Joint Secretary in the Department of Social Welfare of the State Government—member ex officio;
- (e) The State Government shall nominate persons, not below the rank of Joint Secretary in the Departments of Home, Finance and Law to be ex-officio members of State Authority under clause (e) of sub-section (1) of Section 46 of the Act;
- (f) Head of any of the Mental Hospitals in the State or Head of Department of Psychiatry at any Government Medical College, to be nominated by the State Government—member;
- (g) one eminent psychiatrist from the State not in Government service to be nominated by the State Government—member;
- (h) one mental health professional as defined in item (iii) of clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Act as well as sub rule(iii) of 15, of these rules, having at least fifteen years experience in the field, to be nominated by the State Government—member;
- (i) one psychiatric social worker having at least fifteen years experience in the field, to be nominated by the State Government—member;
- (j) one clinical psychologist having at least fifteen years experience in the field, to be nominated by the State Government—member;
- (k) one mental health nurse having at least fifteen years experience in the field of mental health, to be nominated by the State Government—member;
- (l) two persons representing persons who have or have had mental illness, to be nominated by the State Government—member;
- (m) two persons representing care-givers of persons with mental illness or organisations representing care-givers, to be nominated by the State Government—members;
- (n) two persons representing non-governmental organisations which provide services to persons with mental illness, to be nominated by the State Government— members.
- (2) The members referred to in clauses (f) to (n) of rule 4, shall be nominated by the State Government.

**5. Norms for selection of non-official members of State Authority.-**

A person shall not be selected as a non-official member of State Authority unless, he-

- (i) is an Indian National;
- (ii) is of the age not exceeding sixty-seven years;
- (iii) Possesses qualification and experience as specified in rule 5 of Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules 2018.

**6. Invitation of application for the posts of non-official members of State Authority.-** A vacancy for the post of non- official member of the State Authority shall be given wide publicity through open advertisement in at least two daily newspapers (one English and one Local Language) having wide circulation in the State and the advertisement shall also be made available on the website of the Department of Health.

**7. Selection Committee for nomination of non-official members of State**

**Authority.** - The Selection Committee for nomination of non-official members of the State Authority shall consist of a Chairperson who shall be the Chairperson of the State Authority and two independent experts having experience in the field of mental healthcare, to be nominated by the State Government.

**8. Procedure for nomination of non-official members of State Authority.-**

(1) The Selection Committee constituted under rule 7 shall consider all applications received by the Department and scrutinize such applications which fulfill the requirements of Section 46 of the Act and rule 4 and 5 of these rules.

(2) The Selection Committee shall, having regard to the provisions of the Act and these rules, decide about the suitability of the applicants for being selected as members of the State Authority:

Provided that in case of persons to be nominated under sub-rule (3) of rule 5, preference shall be given to the persons with ten years of experience in dealing with persons with mental illness.

(3) The State Government shall nominate the persons selected by the Selection Committee as members of the State Authority.

**9. Terms of office.- (1) Non-official members.-** The members of the State Authority referred to in clauses (f) to (n) of sub-section (1) of section 46 shall hold office as such for a term of three years from the date of nomination and shall be eligible for reappointment:

Provided that a member shall not hold office as such after he has attained the age of seventy years.

(2) **Ex officio members.-** The chairperson and other ex officio members of the State Authority shall hold office as such chairperson or member, as the case may be, so long as he holds the office by virtue of which he is nominated.

(3) **Resignation.-** A non-official member of the State Authority may, by notice in writing under his hand addressed to the State Government, may resign from his office:

Provided that a member shall, unless he is permitted by the State Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as his successor enters upon office or until the expiring of his term of office, whichever is earliest

(4) **Filling of Vacancies.-** The State Government shall, within two month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of a member of the Authority and three months before the superannuation or completion of the term of office of any member of the Authority, make nomination for filling up of the vacancy.

(5) **Allowances for non-official members of State Authority.-** Every non-official member attending the meeting of the State Authority shall be entitled to sitting allowance of rupees two thousand and travelling allowance as well as daily allowance as are applicable to the officers of pay level -11 of the State Government.

- 10. Officers and other employees of State Authority.-** (1) There shall be a chief executive officer of the State Authority, not below the rank of the Deputy Secretary to the State Government, to be appointed by the State Government.
- (2) The State Authority may, with the approval of the State Government, determine the number, nature and categories of other officers and employees required by the State Authority for discharge of its functions.
- (3) The salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service (including the qualifications, experience and manner of appointment) of the chief executive officer and other officers as well as employees of the State Authority shall be such as may be specified by regulations with the approval of the State Government.
- 11. Functions of chief executive officer of State Authority.-**
- (1) The chief executive officer shall be the legal representative of the State Authority and shall be responsible for—
- (a) the day-to-day administration of the State Authority;
- (b) implementing the work, programmes and decisions adopted by the State Authority;
- (c) drawing up of proposal for the State Authority's work programmes;
- (b) the preparation of the statement of revenue and expenditure and the execution of the budget of the State Authority.
- (2) Every year, the chief executive officer shall submit to the State Authority for approval—
- (a) a general report covering all the activities of the Authority in the previous years
- (b) programmes of work;
- (c) the annual accounts for the previous year; and
- (d) the budget for the coming year.
- (3) The chief executive officer shall have administrative control over the officers and other employees of the State Authority.
- 12. Functions of State Authority.-** (1) The State Authority shall—
- (a) register all mental health establishments in the State except those referred to in section 43 and maintain and publish (including online on the internet) a register of such establishments;
- (b) develop quality and service provision norms for different types of mental health establishments in the State;
- (c) supervise all mental health establishments in the State and receive complaints about deficiencies in provision of services;
- (d) register clinical psychologists, mental health nurses and psychiatric social workers in the State to work as mental health professionals, and publish the list of such registered mental health professionals in such manner as may be specified by regulations made by the State Authority;
- (e) train all relevant persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of this Act;
- (f) discharge such other functions with respect to matters relating to mental health as the State Government may decide:

Provided that the mental health establishments in the State (except those referred to in section 43), registered, before the commencement of this Act,

under the Mental Health Act, 1987 or any other law for the time being in force, shall be deemed to have been registered under the provisions of this Act and copy of such registration shall be furnished to the State Authority.

- (2) The procedure for registration (including the fees to be levied for such registration) of the mental health establishments under this section shall be such as may be prescribed by the State Authority.

**13. Meetings of State Authority.-** (1) The State Authority shall meet at such times (not less than four times in a year) and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including quorum at such meetings) as may be specified by regulations made by the State Authority.

- (2) If the chairperson, for any reason, is unable to attend a meeting of the State Authority, the senior-most member shall preside over the meetings of the Authority.

- (3) All questions which come up before any meeting of the State Authority shall be decided by a majority of votes by the members present and voting and in the event of an equality of votes, the chairperson or in his absence the member presiding over shall have a second or casting vote.

- (4) All decisions of the State Authority shall be authenticated by the signature of the chairperson or any other member authorised by the State Authority in this behalf.

- (5) If any member, who is a director of a company and who as such director, has any direct or indirect pecuniary interest in any manner coming up for consideration at a meeting of the State Authority, he shall, as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Authority, and the member shall not take part in any deliberation or decision of the State Authority with respect to that matter.

**14. Furnishing of information.-** The State Government may call for information concerning the activities of the State Authority or the Board periodically or as and when required by it and the State Authority or the Board, as the case may be, shall furnish such information in Form-A.

### CHAPTER-III

#### QUALIFICATION OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS

**15. Mental Health Professionals.-** The State Government shall recognize following professional as “mental health professional”—

- i. a psychiatrist as defined in clause (y) of the Act; or
- ii. a professional registered with the concerned State Authority under section 55 of the Act; or
- iii. a professional having a post-graduate degree (Ayurveda) in Mano Vigyan Avum Manas Roga or a post-graduate degree (Homoeopathy) in Psychiatry or a post-graduate degree (Unani) in Moalijat (Nafasiyatt) or a post-graduate degree (Siddha) in Sirappu Maruthuvam;

**16. Recognition to be Psychiatrist. -** Under clause (y) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, the State Government shall recognize any Medical Practitioner as Psychiatrist possessing a post-graduate degree or diploma in

psychiatry awarded by an university recognized by the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or awarded or recognized by the National Board of Examinations and included in the First Schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) or recognized by the Medical Council of India, constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) National Medical Commission constituted under National Medical Commission Act, 2019( 30 of 2019) and includes any medical officer who having regard to his knowledge and experience in psychiatry has been declared by the State Government to be a psychiatrist for the purposes of this Act;

**17. Qualifications for Clinical Psychologist.-** (1) Under clause (g) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, the qualifications for Clinical Psychologist shall be

- (i) a recognized qualification in Clinical Psychology from an institution approved and recognized, by the Rehabilitation Council of India, constituted under section 3 of the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) or
- (ii) a Post-Graduate degree in Psychology or Clinical Psychology or Applied Psychology and a Master of Philosophy in Clinical Psychology or Medical and Social Psychology obtained after completion of a full time course of two years which includes supervised clinical training from any University recognized by the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and approved and recognized by the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) or such recognized qualification as may be prescribed.

**18. Qualifications for Psychiatric Social Worker.-** Under clause (x) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, the qualifications for Psychiatric Social Worker shall be a post-graduate degree in Social Work and a Master of Philosophy in Psychiatric Social Work obtained after completion of a full time course of two years which includes supervised clinical training from any University recognized by the University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 or such recognized qualification for Psychiatric social work as may be notified in official Gazette by the State Government from time to time for the purposes of this Act.

**19. Mental Health Nurse.-** Under clause (q) of sub-section (1) of Section 2 the qualifications for "Mental Health Nurse" shall be a person with a diploma or degree in general nursing or diploma or degree in psychiatric nursing recognised by the Nursing Council of India established under the Nursing Council of India Act, 1947 and registered as such with the relevant nursing council in the State.

**20. Mental Health Establishment.-** Under clause (p) of sub-section (1) of Section 2 of the Act, a health establishment, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy establishment, by whatever name called, either wholly or partly, meant for the care of persons with mental illness, established, owned, controlled or maintained by the State Government, local authority, trust, whether private or public, corporation, co-operative society, organisation or any other entity or person, where persons with mental



illness are admitted and reside at, or kept in, for care, treatment, convalescence and rehabilitation, either temporarily or otherwise; and includes any general hospital or general nursing home established or maintained by the State Government, local authority, trust, whether private or public, corporation, co-operative society, organisation or any other entity or person; shall be recognized as “Mental Health Establishment” but does not include a family residential place where a person with mental illness resides with his relatives or friends;

- 21. Provisional Registration of Mental Health Professional.**-(1) Every mental health professional in the State shall be registered with the State Authority.
- (2) Every mental health professional referred to in rule 15 above shall submit an application for provisional registration to the State Authority in Form-F, containing details as specified therein, along with a fee, as decided by State Authority.
- (3) The State Authority shall, on being satisfied that the mental health professional fulfils all the requirements as specified in clause (r) of sub-section (1) of section-2 of the Act, grant to such mental health professional, a provisional registration certificate.

#### CHAPTER IV

#### PROVISIONAL REGISTRATION OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS BY STATE AUTHORITY

- 22. Procedure for provisional registration of mental health establishments by State Authority.**-(1) Every mental health establishment in a State, except the mental health establishment under the Control of the Central Government, shall be registered with the State Authority.
- (2) Every mental health establishment referred to in sub-rule (1) shall submit an application for provisional registration to the State Authority in Form-B, containing details as specified therein, along with a fee, as decided by State Authority.
- (3) The State Authority shall, on being satisfied that the mental health establishment fulfils all the requirements as specified in sections 65 and 66, grant to such mental health establishment, a provisional registration certificate in Form-C.
- 23. Validity and renewal of certificate of registration.**- The provisional registration certificate granted under sub-rule (3) of rule 11 shall be valid for a period of twelve months from the date of such grant and an application for renewal of such certificate shall be made in Form-B within thirty days before the date of expiry of the period of validity of such certificate and in case application is not made within the specified period, the mental health establishment concerned shall be liable to pay renewal fee, as decided by State Authority.
- 24. Certification of Regular Registration.**- If a mental health establishment fulfills all the parameters during the provisional registration period and is desirous of regular registration, it may apply to the authority for regular registration in form I along with requisite fee as may be prescribed and the Authority on being satisfied may issue a certificate of regular registration in form C to such establishment which shall be valid for 5 years from the date of license of such certificate.
- 25. Renewal of Regular Registration.**- The regular registration of a mental health establishment may be renewed for five years, if the establishment applies within

six month, prior to the last date of expiration of regular registration in form I, along with the same fee as prescribed for regular registration, otherwise after the expiration of regular registration it shall lapse and the establishment concerned will have to go for provisional registration, afresh.

**26. Issue of duplicate certificate.**-Where a certificate of registration granted to a mental health establishment is destroyed or lost or mutilated or damaged, the State Authority may issue a duplicate certificate on an application made by such establishment along with a fee, as decided by State Authority.

**27. Maintenance of digital register.**- (1) A category-wise register in Form-D of all registered mental health establishments shall be maintained by the State Authority in digital format in accordance with the provisions of Section 71.

(2) A category-wise register in Form-E of all registered mental health professionals shall be maintained by the State Authority in digital format in accordance with the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 55 of the Act.

(3) For application for Registration of Mental Health Professionals along with fees of rupees three thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority in Form-F payable at the place where the State Authority is situated.

(4) Form-G is the format for registration certificate issued to the professionals by the State Mental Health Authority. The registration certificate issued, is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 17) and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of ten years from the date of its issue and can be renewed before one month of the expiry with the prescribed fees.

(5) In fulfillment of the requirement of the Act, the State Authority shall issue regulation or notification with regards to creating and operating online, register of mental health professionals, advanced directives, mental health establishment etc. by taking into account the current laws, standards, rules and regulations for such online databases or portal from time to time.

## CHAPTER V

### FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

**28. Grants by State Government to State Authority.**- The State Government may, after due appropriation made by legislature by law in this behalf, make to the State Authority grants of such sums of money as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

**29. State Mental Health Authority Fund.**- (1) There shall be constituted a Fund to be called the State Mental Health Authority Fund and there shall be credited thereto-

- (i) any grants and loans made to the State Authority by the Central/State Government;
- (ii) all fees and charges received by the State Authority under this Act; and

- (iii) all sums received by the State Authority from such other sources as may be decided upon by the State Government.
- (2) The Fund referred to in sub-rule (1) shall be applied for meeting the salary, allowances and other remuneration of the chairperson, other members, chief executive officer, other officers and employees of the State Authority/Boards and the expenses of the Authority/Boards incurred in the discharge of its functions and for purposes of this Act.

**30. Accounts and audit of State Authority.-** (1) The State Authority shall maintain accounts of its income and expenditure relating to each year and prepare an annual statement of accounts consisting of income and expenditure account and the balance sheet.

- (2) Annual statement of accounts shall be submitted for audit not later than 30th June of each year in the common accounting format prescribed from time to time by the Ministry of Finance for the central autonomous bodies or as nearer thereto as the circumstances admit.
- (3) The annual statement of accounts prepared under sub-rule (1) shall be signed on behalf of the State Authority by the officer in-charge of accounts and the Chief Executive Officer and shall be approved by the State Authority.

**31. Annual report of the State Authority.-** (1) The State Authority shall prepare its annual report in Form-H and forward it to the State Government within nine months of the end of the financial year for being laid before each House of State Legislature.

- (2) The annual report shall give a full account of the activities of the State Authority during the previous year and shall include the audited accounts of the year and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

## CHAPTER VI

### AUDIT, INSPECTION AND ENQUIRY OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS

**32. Audit of Mental Health Establishments.-** (1) The State Authority shall, for the purpose of conducting audit of registered mental health establishments in the State, authorize one or more of the following persons to ensure that such mental health establishments, comply with the minimum standards specified under the Act, namely:-

- (a) A representative of the District Collector/ District Magistrate of the district where the mental health establishment is situated;
- (b) A representative of the State Human Rights Commission;
- (c) A psychiatrist who is in Government service;
- (d) A psychiatrist who is in private practice;
- (e) A mental health professional who is not a psychiatrist;
- (f) A representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;
- (g) Representatives of the care-givers of persons with mental illness or organizations representing care-givers; and

- (h) Representatives of the persons who have or have had mental illness.
- (2) For conducting audit of registered mental health establishment, the State Authority shall charge a fee of **Rs 10,000/- (Rs. Ten Thousand) only** by way of a demand draft drawn in favor of the chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the Authority is situated.

**33. Inspection and inquiry of Mental Health Establishments.-** (1) The State Authority may, suo-motu or on a complaint received from any person with respect to non-adherence of minimum standards specified by or under the Act or on contravention of any provision thereof, order an inspection and inquiry of any mental health establishment, to be made by one or more of the following persons, namely:-

- (a) a psychiatrist in Government service;
- (b) a psychiatrist in private practice;
- (c) a mental health professional who is not a psychiatrist;
- (d) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;
- (e) a police officer in charge of the police station under whose jurisdiction, the mental health establishment is situated;
- (f) a representative of the District Collector/ District Magistrate of the district where the mental health establishment is situated.
- (2) The State Authority or the person authorized by it under sub-rule (1), if it has reasons to, believe that a person is operating a mental health establishment without registration or is not adhering to the minimum standards specified by or under the Act or has been contravening any of the provisions, of the Act or the rules and regulations made there under, enter and search such mental health establishment.
- (3) During search, the State Authority or the person authorized by it may require the mental health professional in charge of the mental health establishment to produce the original documents relating to its registration with the State Authority and it shall be obligatory on the part of the mental health establishment to, produce such documents.
- (4) Within two days of completing search of the mental health establishment under sub-rule (3), a written report of the findings of such search shall be submitted to the Chairperson of the Authority.
- (5) The Chairperson of the State Authority, shall, on receipt of the written report under sub-rule (4), take such action as it deems fit, against the defaulting mental health establishment in accordance with the provisions of the Act.

## CHAPTER VII

### MENTAL HEALTH REVIEW BOARDS

- 34. Constitution of Mental Health Review Boards.-** (1) The State Authority shall, by notification, constitute Mental Health Review Boards in all the 9 (nine) divisions of the State.
- (2) The Boards shall be located in the divisional headquarter.
  - (3) Each Board shall have the jurisdiction over all the districts of the division concerned.

**35. Composition of Board:-** (1) Each Board shall consist of following –

- (a) A District Judge, or an officer of the State Judicial Services to be appointed as District Judge or a retired District Judge, duly nominated by the Hon'ble high court, Patna, who shall be Chairman of the Board;
- (b) Representative of the District Collector or District Magistrate of the districts in which the Board is to be constituted;
- (c) Two members of whom one shall be a psychiatrist and the other shall be a medical practitioner duly appointed by the State Authority;
- (d) Two members who shall be persons with mental illness or care-givers or persons representing organization of persons with mental illness or non- governmental organization working in the field of mental health duly appointed by the State Authority.

**36. Appointment of chairperson and members of Board.-** (1) For the purpose of appointment of the chairperson of the Board under clause (a), and the members of the Board under clauses (c) and (d) of sub-section(1) of section 74, the State Authority shall call for applications by giving wide publicity through open advertisement in at least two daily newspapers (one English and one local language) having wide circulation in the State and the advertisement shall also be made available on the website of the State Authority:

Provided that the District Collector or District Magistrate of the district in which the Board is situated shall nominate its representative as the member of the Board under clause (b) thereof.

- (2) The chief executive officer of the State Authority shall consider all applications received under sub-rule (3) and short list such applications which fulfill the basic eligibility requirements as provided in section 74 and place the same before the Chairperson of the State Authority.
- (3) The appointment of chairperson and members of the Board shall be made by the chairperson of the State Authority in accordance with merit.
- (4) The State Authority shall, three months prior to occurrence of vacancy in the office of chairperson or member of the Board, or where such vacancy arises by reason of death or resignation or removal of such member, initiate the process for filling up such vacancy in a like manner.
- (5) The State Authority shall, from time to time, arrange for the chairpersons and members of the Board to undergo induction training in mental health law, mental healthcare and related areas of not less than two working days.

**37. Term and conditions of service of chairperson and members of Board.-**(1)

The chairperson and members of the Board shall hold office for a term of five years or up to the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for another term of five years or up to the age of seventy years whichever is earlier.

- (2) The appointment of chairperson and members of every Board shall be made by chairperson of the State Authority.

- 38. Honorarium and allowances of chairperson and members of Board.-** (1) If a retired Judge of the District Court is appointed as the Chairperson of the Board, he shall be entitled to a consolidated monthly honorarium which together with the pension or pensionary value of the terminal benefits or both received by such person shall not exceed the last pay drawn by him.
- (2) If a retired government servant is appointed as a member of the Board, he shall be entitled to a consolidated monthly honorarium which together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both received by such person shall not exceed the last pay drawn by him.
- (3) If Chairperson or any member of the Board is in service of the State Government or Central Government, his consolidated honorarium shall be in accordance with the rules applicable to Government servants of his cadre and he shall receive travel allowance only for the day of sitting in the Board.
- (4) Every member of the Board, who is not a servant of the Government, attending the meeting of the Board shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other allowances as are applicable to the officers of pay level - 11 of the State Government.
- (5) No additional pension and gratuity, except as provided in sub-rules (1) and (2), shall be admissible to the chairperson or any member or the Board for service rendered by him to the Board.
- 39. Decisions of Authority and Board—**(1) The decisions of the Authority or the Board, as the case may be, shall be by consensus, failing which by a majority of votes of members present and voting and in the event of equality of votes, the president or the chairperson, as the case may be, shall have a second or casting vote.
- (2) The quorum of a meeting of the Authority or the Board, as the case may be, shall be three members.
- 40. Term of office for chairperson and members of the Board.-** (1) The chairperson and members of the Board shall hold office for a term of five years or up to the age of seventy years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment for a term of five years or up to the age of seventy years whichever is earlier.
- (2) The appointment of chairperson and members of every Board shall be made by the chairperson of the State Authority.
- 41. Powers and Functions of Board.-** (1) Subject to the provisions of the Act, the powers and functions of the Board shall, include all or any of the following matters, namely:—
- (a) to register, review, alter, modify or cancel an advance directive;
- (b) to appoint a nominated representative;
- (c) to receive and decide application from a person with mental illness or his nominated representative or any other interested person against the decision of medical officer or mental health professional in charge of mental health establishment or mental health establishment under section 87 or section 89 or section 90;
- (d) to receive and decide applications in respect non-disclosure of

- information specified under sub-section (3) of section 25;
- (e) to adjudicate complaints regarding deficiencies in care and services specified under section 28;
- (f) to visit and inspect prison or jails and seek clarifications from the medical officer in-charge of health services in such prison or jail
- (2) Where it is brought to the notice of a Board or State Authority, that a mental health establishment violates the rights of persons with mental illness, the Board or the Authority may conduct an inspection and inquiry and take action to protect their rights.
- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, the Board, in consultation with the Authority, may take measures to protect the rights of persons with mental illness as it considers appropriate.
- (4) If the mental health establishment does not comply with the orders or directions of the Authority or the Board or wilfully neglects such order or direction, the Authority or the Board, as the case may be, may impose penalty which may extend up to five lakh rupees on such mental health establishment and the Authority on its own or on the recommendations of the Board may also cancel the registration of such mental health establishment after giving an opportunity of being heard.

**42. Meetings.-** The Board shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be specified by the State Authority.

**43. Appeal to High Court against order of Authority or Board.-** Any person or establishment aggrieved by the decision of the Authority or Board may, within a period of thirty days from such decision, prefer an appeal to the High Court of the State:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of thirty days

## CHAPTER VIII MISCELLANEOUS

**44. (1)** The State Authority under section-123 of the Act may, by notification, make regulations, consistent with the provision of this Act and the rules made there under, to carry out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely.-

- (i) the minimum quality standards of mental health services under sub-section(9) of section 18;
- (ii) the salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service (including the qualification, experience and manner of appointment) of the chief executive officer and other officers and employees of the State Authority under sub-section (3) of section 52;
- (iii) the manner in which the State Authority shall publish the list of registered mental health professionals under clause (d) of sub-section (1) of section 55;

- (iv) the times and places of meetings of the State Authority and rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting (including quorum at such meetings) under sub-section (1) of section 56;
  - (v) the form of application to be made by the mental health establishment and the fees to be accompanied with it under sub-section (12) of section 66;
  - (vi) the manner of filing objections under sub-section (14) of section 66;
  - (vii) any other matter which is required to be, or may be, specified by regulations or in respect of which provision is to be made by regulations.
- 45.** Every rules made by the State Government and every regulation made by the State Authority under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made before each House of the State Legislature under sub section (2) of section 124 of the Act.
- 46.** Any action taken or any Authority or Board constituted consistent with the provisions of the Act prior to the commencement of these rules, shall be deemed to be taken or constituted under these rules.

By order of the Governor of Bihar.

Sd/-Illigible,  
Secretary of Govt.



FORM-A  
(See rule 17)  
INFORMATION ON THE ACTIVITIES OF THE STATE  
AUTHORITY

1. New Regulations notified;
2. Number of orders passed during the year;
3. Meetings held during the year;
4. Number and details of mental health establishments under the control of the State Government;
5. Number and details of mental health establishments in the State;
6. Registration of mental health professionals by the State Authority;
7. Statement on references received from the Central Government and the State Government and action taken thereon;
8. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government;
9. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017);
10. Applications for registration of mental health establishments received accepted and rejected along with reasons for such rejection;
11. Audit of Mental Health Establishments along with audit reports;
12. Complaints received regarding violation of rights of mentally ill Persons and action taken thereon;
13. Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals;
14. Details of inspection and inquiry of Mental Health Establishments;
15. Number of appeals to High Court against order of Authority and status thereof;
16. Complaints received regarding deficiencies in provision of services and action taken thereon;
17. Stakeholders Consultations;
18. Inquiry initiated by the Authority/Board;
19. Administration and establishment matters;
20. Budget and Accounts with details including balance sheet, income and expenditure account, etc;
21. Any other matter which may be relevant;

## FORM-B

[See rules 22(2) and 23]

APPLICATION FOR GRANT OF PROVISIONAL REGISTRATION RENEWAL  
OF PROVISIONAL REGISTRATION OF A MENTAL  
HEALTH ESTABLISHMENT

To,

The State Mental Health Authority,  
State Institute of Health and Family Welfare (SIHFW),  
Sheikhpura, Patna, Bihar.

Dear Sir/Madam,

I/we intend to apply for grant of provisional registration/permanent registration/renewal of provisional registration for the Mental Health Establishment namely..... of which I am/we are holding a valid license/registration for the establishment/maintenance of such hospital/nursing home. Details of the hospital/nursing home are given below:

1. Name of applicants.....
2. Details of license with reference to the name of the authority issuing the license and date: .....
3. Age:.....
4. Professional experience in Psychiatry:.....
5. Permanent address of the applicant:.....
6. Location of the proposed hospital/nursing home: .....
7. Address of the proposed nursing home/hospital: .....
8. Proposed accommodations:
  - (a) Number of rooms: .....
  - (b) Number of beds: .....
  - (c) Facilities provided: .....
  - (d) Out-patient: .....
  - (e) Emergency services: .....
  - (f) In-patient facilities: .....
  - (g) Occupational and recreational facilities: .....
  - (h) ECT facilities and X-Ray facilities: .....
  - (i) Psychological testing facilities: .....
  - (j) Investigation and laboratory facilities: .....
  - (k) Treatment facilities staff pattern: .....

**Staff Pattern**

- (a) Number of doctors:.....
- (b) Number of nurses:.....
- (c) Number of attendees: .....
- (d) others: .....

I am herewith sending a bank draft for Rs.....  
drawn in favor of .....as application fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulation  
of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the  
license for establishment/maintenance of psychiatric hospital/ nursing  
home.

Yours faithfully

Signature

Name .....

Date .....

FORM-C

[See rule 23(3)]

**CERTIFICATE OF PROVISIONAL/REGULAR REGISTRATION/  
RENEWAL OF PROVISIONAL/REGULAR REGISTRATION**

The State Authority, after considering the application dated.....submitted by.....under Section 65 (2) or Section 66 (3) or Section 66(10) of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), hereby accords provisional/regular registration/ renewal of provisional/regular registration to the applicant mental health establishment in terms of Section 66 (4) or section 66 (11) and Rule 23(3) as per the details given hereunder:

Name: \_\_\_\_\_

Address : \_\_\_\_\_

No. of Beds: \_\_\_\_\_

The provisional registration certificate issued is subject to the conditions laid down in the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017) and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of twelve months from the date of its issue and can be renewed.

Place:

Date:

Registration Authority  
Seal of the Registration Authority

**FORM-D**

(See rule 26)

**REGISTER OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS  
(IN DIGITAL FORMAT)**

Separate table for each category of mental health establishment

Category-----

Sl. No	Name & address of the applicant	Name of the establishment and address	Date of the application	Date and particulars of registration	No. of beds	Remarks

**FORM-E**

[See rule 26(2)]

(Separate table for each category of mental health professionals)

Category of Mental Health Professionals -----

Sl. No	Full Name & address of the applicant	Qualification/ Institute	Registration No.	Place of practice/ work	Contact Number / Email	Remarks

\*the Psychiatric Social Workers will be registered as the MentalHealthcare Act, 2017 (10 of 2017), shall prescribed.

**FORM-F**

[see rules 26(3)]

**APPLICATION FOR GRANT OF REGISTRATION/ RENEWAL OF  
REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH PROFESSIONAL**

To,

The State Mental Health Authority,  
State Institute of Health and Family Welfare (SIHFW),  
Sheikhpura, Patna, Bihar.

Dear Sir/Madam,

I intend to apply for grant of registration/ renewal of registration for the Mental Health Professionals in following sub-category,

Category of Mental Health Professionals -----

Sl. No	Full Name & address of the applicant	Qualification/ Institute	Registration No. And Year	Place of practice/ work	Contact Number / Email	Remarks
	1. Name-					
	2.Address for correspondence-					
	3.Permanent Address-					

I am herewith sending a bank draft for Rs..... drawn in favour of .....as application fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the registration for the Mental Health Professional to practice in Bihar State.

Yours faithfully  
Signature  
Name  
Dated

\*this is not applicable for Psychiatric Social Worker

**FORM-G**

[See rules 26(4)]

**CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF  
PROVISIONAL REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH PROFESSIONAL**

The State Authority, after considering the application dated..... .submitted by .....under Section 55 (1) (d) of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), hereby accords registration/renewal of registration to the applicant, as mental health professionals category.....

Registration No: - -----

Name:-----

Address -----

The registration certificate issued is subject to the conditions laid down in the Mental Health care Act, 2017 (10 of 2017) and the rules and regulations made there under and shall be valid for a period of ten years from the date of its issue and can be renewed.

Place:

Date:

Registration Authority  
Seal of the Registration Authority

**FORM-H**  
[see rules 18(1)]

**ANNUAL REPORT OF STATE AUTHORITY**

1. Introduction
2. Profile of the Authority's Members
3. Scope of Regulation
4. New Regulations/procedures etc. notified/ issued
5. Orders passed by the Authority
6. Meetings of the State Mental Health Authority held during the year
7. Mental health establishments under the control of the State Government
8. Mental health establishments in the State
9. Registration of mental health professionals by the State Authorities
10. A statement on references received from Central and State Governments and action taken thereon
11. A statement on references sent to the Central and State Governments and action taken thereon by the respective Governments
12. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government
13. Supervision of mental health establishments under the State Government and action taken on the complaints received about deficiencies in provision of services therein
14. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017)
15. Applications for registration of mental health establishments received accepted and rejected along with reasons for such rejection.
16. Audit of Mental Health Establishments
17. Complaints received regarding violation of rights of Mentally ill persons and action taken thereon
18. Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals
19. Implementation of RTI Act, 2005 (No. 22 of 2005)
20. Details regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under Section 22 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (No. 14 of 2013).
21. Inspection and Inquiry of Mental Health Establishments
22. Appeals to High Court against order of Authority and status thereof
23. Status of review of use of advance directives and recommendations of the Authority in respect thereof.
24. Complaints received about deficiencies in provision of services and action taken thereon.
25. Inquiry initiated by the Authority
26. Administration and establishment matters
27. Annual Accounts
28. Any other-matter which in the opinion of the Authority needs to be highlighted

## FORM-I

[See rules 24 &amp; 25]

APPLICATION FOR GRANT OF REGULAR REGISTRATION/RENEWAL OF  
REGULAR REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH ESTABLISHMENT

To,

The State Mental Health Authority,  
State Institute of Health and Family Welfare (SIHFW),  
Sheikhpura, Patna, Bihar.

Dear Sir/Madam,

I/we intend to apply for grant of regular registration/renewal of regular registration for the Mental Health Establishment namely..... of which I am/we are holding a valid license/registration for the establishment/maintenance of such hospital/nursing home. Details of the hospital/nursing home are given below:

1. Name of applicants.....
2. Details of Provisional/Regular Registration Certificate with reference to the name of the authority issuing the Certificate of Registration and date:.....
3. Age:.....
9. Professional experience in Psychiatry:.....
10. Permanent address of the applicant:.....
11. Location of the proposed hospital/nursing home: .....
12. Address of the proposed nursing home/hospital: .....
13. Proposed accommodations:
  - (a) Number of rooms: .....
  - (b) Number of beds: .....
  - (c) Facilities provided: .....
  - (f) Out-patient: .....
  - (g) Emergency services: .....
  - (f) In-patient facilities: .....
  - (l) Occupational and recreational facilities: .....
  - (m) ECT facilities and X-Ray facilities): .....
  - (n) Psychological testing facilities: .....
  - (o) Investigation and laboratory facilities: .....
  - (p) Treatment facilities staff pattern: .....

**Staff Pattern**

- (e) Number of doctors:.....
- (f) Number of nurses:.....



(g) Number of attendees: .....

(h) others: .....

I am herewith sending a bank draft for Rs..... drawn in favor of .....as application fee.

I hereby undertake to abide by the rules and regulation of the Mental Health Authority.

I request you to consider my application and grant the license for establishment/maintenance of psychiatric hospital/ nursing home.

Yours faithfully

Signature

Name .....

Date .....

\_\_\_\_\_  
अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 392-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>